

मनरेगा और ग्रामीण परिवर्तन : जनपद सीतापुर का अध्ययन

रजनीकान्त श्रीवास्तव^{1a}

^aसहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, आर०एम०पी० (पी०जी०) कालेज, सीतापुर, उ०प्र०, भारत

ABSTRACT

मनरेगा का उद्देश्य भारत में न सिर्फ ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना बल्कि उनके काम करने के अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करना है। यह एक बहु उद्देशीय योजना है, जो एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर हो रहे पलायन को रोकने में प्रभावी होगी वही ग्रामीणों को अपने ही गांव में कार्य दिलाने, उनकी आय में वृद्धि करने, एवं गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास और ग्रामीण सुन्दरीकरण में सहायक होगी।

KEYWORDS: ग्रामीण परिवर्तन, ग्रामीण विकास योजनायें, वेरोजगारी उन्मूलन, रोजगार गारंटी

25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम किया गया। 02 फरवरी 2006 में इसे 200 जिलों में और 01 अप्रैल 2008 से इसे भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। इस योजना में एक वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। योजना के लागू होने से अब तक इसके समर्थन और विपक्ष में बुद्धिजीवियों द्वारा अलग-अलग प्रकार से प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। उषा रानी त्यागी एवं आहूजा, दुष्यंत चौहान, सोनिया चौधरी ने अपने शोध Impact of MGNREGA on Rural employment and Emigration : A Study in Agriculturally- back ward and agriculturally advanced district of Haryana में करनाल (कृषि में अग्रणी) तथा मेवाती (कृषि में पिछड़ा) जिलों से 60-60 परिवारों का चयन करके उनकी आय रोजगार, सुरक्षा, कर्ज, भुगतान जैसे विषयों पर मनरेगा के प्रभावों का विश्लेषण किया है। शोध के परिणाम बताते हैं कि मनरेगा द्वारा रोजगार के अवसर के बावजूद नगरों में उच्च मजदूरी के लालच में ग्रामीणों का पलायन जारी है। शोध से यह भी ज्ञात हुआ कि बड़ी भूमियों, पशुधन के स्वामी ग्रामीणों की मनरेगा कार्यों में अधिक रुचि नहीं है।

डा० सुधीर कुमार एवं शिवानी वर्मा डी०एन० कालेज, मेरठ ने अपने शोध लेख MGNREGA: A Step towards Ruler

Development (2014) मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन किया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद सीतापुर में ग्रामीणों के जीवन पर मनरेगा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश के मध्य में लखनऊ मण्डल का एक भाग है जो लखनऊ से उत्तर में 27° 6" व 27° 54" अक्षांश तथा पूर्व में 80° 18" व 81° 24" देशान्तर के मध्य स्थित है। सीतापुर की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और भौगोलिक दृष्टि से इसकी गणना तराई क्षेत्र में होती है।

शोध पत्र में दो ग्रामीण वर्गों के विचारों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गये हैं। एक वर्ग ऐसे उत्तरदाताओं का है जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत अधिकतम कार्य किया है। दूसरे वर्ग में वह उत्तरदाता हैं जिन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत बिल्कुल कार्य नहीं किये हैं। शोध पत्र निम्न प्रश्नों पर क्रेन्द्रित है:

1. जाब कार्ड बनवाने, कार्य प्राप्त करने और भुगतान के बारे में लोगो की क्या राय है?
2. गाँव के विकास और सुन्दरीकरण पर दोनों वर्गों की क्या राय है?
3. गाँव में मनरेगा से हो रही आय के क्या दुष्प्रभाव हुए हैं?
4. आर्थिक सशक्तिकरण में मनरेगा की क्या भूमिका रही है?

सारणी-1 (उत्तरदाताओं की स्थिति)

शोध प्रविधि:-

यह शोध अनुभव मूलक है और सर्वेक्षण की पद्धति पर आधारित है। शोध

क्र०सं०	तहसील	योग	लिंग		धर्म		व्यवसाय			कार्य की स्थिति	
			पु०	स्त्री	हिन्दू	अन्य	कृषि	स्वयं का	श्रमिक	अधिकतम कार्य	न्यूनतम कार्य
1	सीतापुर	10	5	5	8	2	3	0	7	6	4
2	महोली	10	5	5	8	2	3	0	7	4	6
3	लहरपुर	10	5	5	6	4	2	1	7	6	4
4	मिश्रिख	10	5	5	10	0	3	2	5	5	5
5	महमूदाबाद	10	5	5	8	2	3	1	6	4	6
		50	25	25	40	10	14	4	32	25	25

के लिए जनपद सीतापुर की पाँच तहसीलों- सीतापुर, महोली,

मिश्रिख, महमूदाबाद, और लहरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक तहसील से दस परिवारों का चयन दैव निदर्शन प्रणाली

श्रीवास्तव : मनरेगा और ग्रामीण परिवर्तन : जनपद सीतापुर का अध्ययन

द्वारा किया गया। प्रत्येक तहसील से चुने गये 10 परिवारों में पाँच ऐसे परिवार हैं जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में मनरेगा में अधिकतम कार्य प्राप्त किया है जबकि शेष 5 परिवारों का कार्य लगभग नहीं के बराबर है। इस प्रकार दोनो वर्गों के 25-25 परिवारों से प्रश्नावली के द्वारा मनरेगा के प्रभावों संबंधी प्राथमिक सूचनाओं का संकलन और वर्गीकरण करके तथ्यों का सांख्यिकी द्वारा वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कुछ मौलिक निष्कर्ष निकाले गये हैं।

सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक तहसील से 10 परिवारों का चयन किया गया है जिनमें 5 परिवारों में उत्तरदाता महिलाएँ हैं और

शेष 5 में पुरुष उत्तरदाता है, इस प्रकार सर्वेक्षण में 25 पुरुष और 25 महिला उत्तरदाता है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के हैं और 20 प्रतिशत अन्य धर्म के। उत्तरदाताओं में 64 प्रतिशत श्रमिक वर्ग से हैं जबकि 28 प्रतिशत कृषक वर्ग से हैं। 8 प्रतिशत उत्तरदाता निजी व्यवसायगत हैं। 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा का अधिकतम कार्य प्राप्त किया है जबकि 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने न के बराबर कार्य किया है।

सारणी -2 जाब कार्ड, कार्य स्थिति एवं भुगतान पर दृष्टिकोण									
क्रम	चर	राय	अधिकतम कार्य वर्ग	%	न्यूनतम कार्य वर्ग	%	योग	%	Chi -Sq
1	जाब कार्ड बनवाने में प्रधान की मर्जी सवोपरि है?	Y	5	20	22	88	27	54	.000**
		N	20	80	3	12	23	46	
2	कार्य दिलवाना पूर्णता प्रधान की इच्छा पर है?	Y	0	0	20	80	20	40	.000**
		N	25	100	5	20	30	60	
3	भुगतान प्राप्त होना ग्राम प्रधान की इच्छा पर है?	Y	4	16	20	80	24	48	.000**
		N	21	84	5	20	26	52	

Y=हाँ, N=नहीं, ** → Significant at 1 % level

नोट : → प्रत्येक वर्ग में उत्तरदाताओं द्वारा चयनित विकल्प का प्रतिशत

सारणी से यह स्पष्ट है कि 54 प्रतिशत परिवार यह मानते हैं कि जाब कार्ड का बनना ग्राम प्रधान की मर्जी पर निर्भर है। जबकि 46 प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत हैं। अधिकतम कार्य करने वाले वर्ग में 80 प्रतिशत श्रमिक इस बात से असहमत हैं जबकि कार्य न करने वाले वर्ग में 88 प्रतिशत श्रमिक मानते हैं कि जाब कार्ड का बनना प्रधान की इच्छा पर निर्भर है। शायद इन

लोगों का जाब कार्ड प्रधान के कारण ही नहीं बन पाया प्रतीत होता है, इसकी वजह से इनका मनरेगा में कार्य भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। सारणी से साफ देखा जा सकता है कि काम न पाने वाले वर्ग के 80: उत्तरदाता मान रहे हैं कि मनरेगा में कार्य मिलना भी प्रधान की मर्जी पर निर्भर है। शायद यही कारण है कि जिन लोगो में अधिकतम कार्य प्राप्त किया है, उनमें एक भी व्यक्ति प्रधान को इसके लिए उत्तरदायी नहीं मानता। दोनो वर्ग के मत परस्पर विपरीत हैं जो निश्चय ही ग्राम प्रधान की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

सारणी -3 मनरेगा द्वारा गांव के बदलाव और विकास पर दृष्टिकोण									
क्रम	चर	राय	अधिकतम कार्य वर्ग	%	न्यूनतम कार्य वर्ग	%	योग	%	Chi -Sq
4	सड़को की स्थिति में सुधार?	Y	8	32	3	12	11	22	.085*
		N	17	68	22	88	39	78	
5	गांव की स्वच्छता में वृद्धि?	Y	4	16	2	8	6	12	.334
		N	21	84	23	92	44	88	
6	वृक्षारोपण में वृद्धि?	Y	1	4	0	0	1	2	.500
		N	24	96	25	100	49	98	
7	जल संरक्षण के उपायो का संवर्द्धन	Y	21	84	15	60	36	72	.057*
		N	4	16	10	40	14	28	

Y=हाँ, N=नहीं, * → Significant at 10 % level नोट :
→ प्रत्येक वर्ग में उत्तरदाताओं द्वारा चयनित विकल्प का प्रतिशत

इस सारणी में गांव में मनरेगा के तहत हुए विकास और सुन्दरीकरण के बारे में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि दोनो ही वर्गों के उत्तरदाताओं का बहुमत स्वीकार कर रहा है कि गांव में सड़को की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं माना है। इसी प्रकार कुल मतदाताओं का 88 प्रतिशत मानते हैं कि मनरेगा कार्यों से गांव में कोई स्वच्छता नहीं आयी है। यह देखना भी दुःखद है कि कुल उत्तरदाताओं के 98 प्रतिशत का मत है कि गांव में मनरेगा के

तहत वृक्षारोपण कार्य भी नहीं हुए हैं। एक मात्र सकारात्मक पक्ष जिसमें मनरेगा का प्रभाव दिखाई देता है वह गांव में जल संरक्षण के उपायो से सम्बन्धित है। 72 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि मनरेगा के तहत हुए कार्यों से जल संरक्षण की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। विश्लेषण से जो रोचक तथ्य सामने आता है कि जिन लोगो ने मनरेगा में अधिकतम कार्य किया है वे भी यह मानते हैं कि मनरेगा के कार्य से गांवों में विकास या सुन्दरीकरण नहीं हो पाया है, जो निश्चय ही योजना के लिए अच्छा संकेत नहीं है और जनता के धन से संचालित हो रही इस योजना में अरबों रूपयों के व्यय पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

सारणी -4 मनरेगा की आय के गांवों पर दुष्प्रभाव सम्बन्धी दृष्टिकोण									
क्रम	चर	राय	अधिकतम कार्य वर्ग	%	न्यूनतम कार्य वर्ग	%	योग	%	Chi Sq
8	तम्बाकू के सेवन व धूमपान में वृद्धि?	Y	20	80	18	72	38	76	.371
		N	5	20	7	28	12	24	
9	शराब के सेवन में वृद्धि?	Y	16	64	22	88	38	76	.048*
		N	9	36	3	12	12	24	
10	जुए की प्रवृत्ति को बढ़ावा?	Y	18	72	24	96	42	84	.024*
		N	7	28	1	4	8	16	
11	मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि?	Y	6	24	18	72	24	48	.001**
		N	19	76	7	28	26	52	

Y=हाँ, N=नहीं, * → Significant at 10 % level ** → Significant at 1 % level

नोट : → प्रत्येक वर्ग में उत्तरदाताओं द्वारा चयनित विकल्प का प्रतिशत

इस सारणी से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि मनरेगा से बढ़ती आय ने गांवों में दुष्प्रवृत्तियों को किस प्रकार बढ़ावा दिया है। 76 प्रतिशत उत्तरदाता मान रहे हैं कि गांवों में विगत वर्षों में मदिरा पान बढ़ा है रोचक तथ्य यह है कि जो लोग मनरेगा में अधिकतम कार्य कर रहे हैं उनमें से 64 प्रतिशत लोगों का मानना है कि मनरेगा से हुई आय ने गांवों में मदिरा पान को बढ़ावा दिया है वही काम न करने वाले 88: लोग भी मान रहे हैं कि गांवों में विगत वर्षों में मदिरा पान बढ़ा है।

यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि जो लोग मनरेगा में कार्य नहीं कर रहे हैं वे अपने को खाली समय में शराब जैसी प्रवृत्तियों की ओर मोड़ रहे हैं। दोनों ही वर्ग के उत्तरदाताओं का मानना है कि गांवों में जुए का खेला जाना बढ़ा है। कार्य करने वालों में 72 प्रतिशत व न करने वालों में 96 प्रतिशत लोग मानते हैं कि जुए की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह कि जो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं उनमें 72 प्रतिशत लोग मान रहे हैं कि गांव में नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ा है। समाज और सरकार के लिए यह चिंताजनक है। कार्य करने वाले लोगों के मात्र 24 प्रतिशत ही मानते हैं कि उनके परिवारों में नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ा है।

सारणी -5 मनरेगा द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण पर दृष्टिकोण									
क्रम	चर	राय	अधिकतम कार्य वर्ग	%	न्यूनतम कार्य वर्ग	%	योग	%	Chi -Sq
12	बचत में वृद्धि?	Y	7	28	0	0	7	14	.005**
		N	18	72	25	100	43	86	
13	छोटे कर्जों से मुक्ति?	Y	15	60	0	0	15	30	.000**
		N	10	40	25	100	35	70	

Y=हाँ, N=नहीं,* → Significant at 10 % level ** → Significant at 1 % level

नोट : → प्रत्येक वर्ग में उत्तरदाताओं द्वारा चयनित विकल्प का प्रतिशत

इस सारणी में परिणाम एक पक्षीय किन्तु बहुत ही स्पष्ट है कि अधिकतम कार्य पक्ष के 72 प्रतिशत एवं कार्य न करने वाले वर्ग के शतप्रतिशत लोग इस बात से असहमत हैं कि मनरेगा की आय ने उनकी बचत क्षमता को बढ़ाया है। इसका कारण सम्भवतः ग्रामीणों की आय से अधिक व्यय और बढ़ती हुई महगाई हो सकती है। यद्यपि कार्य न करने वालों की तुलना में अधिकतम कार्य वर्ग के 28: लोग अपनी बचत बढ़ने की बात से सहमत हैं। तथ्यों के विश्लेषण से ये सकारात्मक निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतम कार्य वर्ग के 60: लोगों ने माना है कि वे मनरेगा की आय के कारण छोटे-छोटे कर्जों से उभरने में सफल हुए हैं। जबकि कार्य न करने वालों में ऐसा मानने वालों का प्रतिशत शून्य है।

निष्कर्ष

1. मनरेगा में ग्राम प्रधान बहुत ही प्रभावी भूमिका में है। जाबकार्ड बनवाने और कार्य दिलाने में उनकी इच्छा सर्वोपरि है और शायद उनके पक्ष के लोग ही अधिक लाभान्वित हैं।
2. शोध से ज्ञात हुआ कि मनरेगा कार्यों से गांवों की सड़को और स्वच्छता में कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही वृक्षारोपण को बढ़ावा मिला है। मनरेगा कार्य मुख्यतः कुओ और तालाबों के निर्माण तक ही सीमित रह गए हैं।
3. मनरेगा से हुई आमदनी ने एक ओर गांव में शराब और जुओ की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है वही दूसरी ओर कार्य न पाने वाले लोगों में निराशा और उनका खाली रहना उन्हें शराब, जुए के साथ-साथ उन्हें नशीले पदार्थों के सेवन की ओर भी प्रवृत्त कर रहा है।
4. मनरेगा की आय ने लोगों को छोटे ऋणों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। किन्तु मनरेगा की आय इतनी भी अधिक नहीं है कि लोगों की बचत में प्रभावी वृद्धि हो सके।

श्रीवास्तव : मनरेगा और ग्रामीण परिवर्तन : जनपद सीतापुर का अध्ययन

सुझाव:-

1. जब कार्ड बनाने का काम छण्ळण्ळ अथवा किसी संस्था के जिम्मे किया जा सकता है जिससे इसमें प्रधानों का वर्चस्व समाप्त हो सके।
2. लोगो को स्वेच्छा से किन्तु अनिवार्यतः मनरेगा में काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि ताकि सभी ग्रामीणों के लिए रोजगार सुनिश्चित हो सके।
3. मनरेगा में विभिन्न प्रकार के कार्यों का कराया जाना सुनिश्चित हो ताकि यह योजना केवल तालाबों और जलाशयों खुदाई तक ही यह सीमित न रहे।
4. लोगो को बचत योजनाओं और आर्थिक नियोजन के बारे में जानकारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
5. गांव में अशिक्षा वहाँ फैलने वाली दुष्प्रवृत्तियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अतः प्रौढ़ वर्ग के लोगो को

भी नशाखोरी, जुएँ और मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए।

संदर्भ

- कदम, राजेश, सुमित भंडारी एवं गोदावरी पवार, (2015) *महात्मा गांधी नेशनल रुरल इम्प्लायमेन्ट गारंटी एक्ट* लैप लैम्बर्ड एकेडमिक पब्लिशिंग डाट काम ।
- पुरोहित, अशोक (2014), *मनरेगा और ग्रामीण विकास* नई दिल्ली, डोमिनेन्ट पब्लिशर्स
- सीतापुर विकास पुस्तिका 2014, *जिला अर्थ एवं साँख्यिकी विभाग।*
- नरेप्पा नागराज एवं बी0जी0 हरीश (2012) *ऐन इकोनोमिक इम्पैक्ट एनालिसिस आफ मनरेगा* लैप लैम्बर्ड एकेडमिक पब्लिशिंग डाट काम